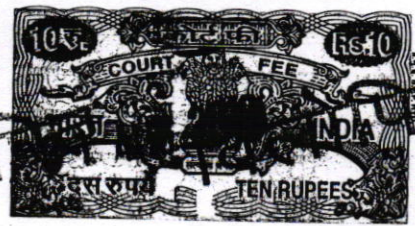


57



न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कुरवाड़े

जिला विदिशा मध्य प्रदेश

प्र. करण क्रमांक - 1201/मिगरानी-3211/2018/विदिशा/प्र.क

अनुराग शर्मा पुत्र स्व. कृष्ण शर्मा
निवासी ग्राम ककरावली तह.पठारी
जिला विदिशा म.प्र.

-- प्राधी

बनाम

दिलीप सिंह चन्देल पुत्र दिनेशचन्द
निवासी ककरावली मकान न.93
शिवावलीका कानोनी पसे न.-1 छाजूरु
कला रोड पिपलानी भोपाल

--- प्रतिप्राधी

निगरानी वि.सू. आदेश दिनांक 5.3.18 पारित

न्यायालय तहसीलदार प्रकरण क्रमांक 008/अ-6/17-18

ग्राम ककरावली अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.सू.रा.सहित

श्रीमान जी,

प्राधी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है

यह कि, अमानिस्था न्यायालय का आदेश विपरीत विधान
सर्व प्रकरण पत्रवाली के वि.सू. होने से निरस्त किये जाने
योग्य है।

2- यह कि अमानिस्था न्यायालय प्रकरण में नामांतरण प्रकिया

का पालन ना कर प्राधी की आपीट पर प्रथम
निराकरण ना कर प्रकरण में नामांतरण आदेश करना
चाहते है इस हेतु प्राधी ने अपनी लिखात आपीट
दिनांक 16.1.18 को प्रस्तुत की प्राधी जिसका जबाब
अनापेक्षक द्वारा दिनांक 7.2.18 को प्रस्तुत किया जइ
पुका उक्त आपीट पर दिनांक 5.3.18 को सुनवाई कर
प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया किन्तु कोई आदेश
पारित ना कर प्रकरण में लम्बान किया जा रहा है।

श्री 20 को मगवान का
द्वारा आज दि. 25.5.18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 6.6.18 नियत।
पलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

25-5-18
A. K. Sharma


3

निगरानी वि.सू. आदेश प्राधी की कानोनी पेचदगी में नामांतरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3211/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/06/2018	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अनेक न्यायदृष्टांत एवं विक्रय-पत्र की मूल प्रति पेश की जाकर छायाप्रति पर सत्यापन करते हुए प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया था। जिसमें अगली सुनवाई दिनांक को आपत्ति पेश हो जाने से प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जा रही है, जिसमें हस्तक्षेप का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	